R

Samyak
An Institute For Civil Services

RAS - 23 MAINS TEST SERIES

सिद्धि-II - 009

Time : 3 Hours | **Maximum Marks : 200**

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राज्य राजनीति, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले
Indian Political System, World Politics and Current Affairs

Paper - III (Unit - I)

Name :		MARKS	
Enroll. No.:	Part	Attempted Questions	Marks Obtained
Date of Birth : 20-01-2002	Part - A	22	32
Medium : Hindi	Part - B	15	56
E-mail :	Part - C	7	48
Exam Date :	Total	44	136
Invigilator's Signature :			
ECN: RCN:	Hindi: 9	English: 0	

अनुदेश (Instructions)

1. परीक्षा शुरू होने से पहले पुस्तिका को जाँच लें।
   Please check the booklet before commencement of the exam.
2. अंक योजना प्रत्येक खंड के प्रारम्भ में दी गई है।
   The marking scheme is given at the start of every section.
3. अभ्यर्थियों को उत्तर निर्धारित शब्द सीमा से अधिक नहीं लिखना चाहिए, इसका उल्लंघन करने पर अंक काटे जा सकते हैं।
   Candidates should not write more than the prescribed word limit in answers, violating this may result in deduction of marks.
4. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही लिखें। बॉर्डर लाईन से बाहर प्रत्युत्तर नहीं लिखें। बॉर्डर लाईन के बाहर लिखे गये उत्तर को जाँचा नहीं जायेगा।
   Candidates are directed to write answers only in the prescribed space of booklet. They should not write answer outside the border line. Answer written outside the border line will not be checked.

SAMYAK, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur, 9875170111
Test Series Helpline & Whatsapp - 9414988860, Email Id - samyaktestseries@gmail.com

	REVIEW PARAMETERS	SCALE			
		Good	Above Average ✓	Average	Below Average
1.	DOES THE ANSWER ADDRESS THE DEMAND OF THE QUESTION?				
a.	Answer Relevancy		✓		
b.	**Answer Enrichment** points like use of: · **Key Terms**/ Subject Vocabulary. Use of Commission/ report/ government publication/ judgements, etc. **Association with the Current Affairs** and **use of examples** to explain the concept and idea		✓ ✓		
2.	HOW WELL IS THE ANSWER PRESENTED?				
a.	**Structure** - Intro, Body, Conclusion		✓		
b.	**Presentation** – Using Subheadings/ points/ highlighting/ flowcharts/ diagrams/ maps		✓		
c.	**Language & Grammar**		✓		
d.	**Word limit**			✓	

Detailed Comments / Feedback / Suggestions for Improvement
विस्तृत टिप्पणियाँ/फीडबैक/सुधार के लिए सुझाव

1. आपका Basic क्लीयर है ~~आपको~~ अब बार-बार रिविजन करो।
2. शब्द सीमा का ध्यान रखो।
3. ~~तर्कों~~ ~~व~~ निष्कर्ष को लिखो।
4. सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करो।
5. समसामयिक मामलो पर ध्यान दो।
6. English व हिन्दी पर विशेष ध्यान दो।

Part - A

Note : Answer the following questions in 15 words. Each question carries 2 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 15 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

1. राजस्थान मे स्थानीय स्वशासन के सन्दर्भ में गठित समितियों का नाम उल्लेखित कीजिये।
Mention the names of the committees formed in the context of local self-government in Rajasthan.

1/2

1. सादिक अली समिति (2) हरलाल खर्रा समिति
2. भैरोसिंह शेखावत समिति (3) गिरधारी लाल व्यास समिति
3. बलवन्तराय मेहता समिति, केन्द्र सरकार की समिति
(4) कटारिया समिति

(Write above this line only)

2. 'नागरिक समाज' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Civil Society'.

2

नागरिक समाज से तात्पर्य सरकार एवं व्यावसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो जनकल्याण एवं जन सेवा के लिए कार्य करते हैं। ये सरकार व आमजनता के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। उदा.- NGO, महिला संगठन, किसान संघ, आदि। मीडिया

(Write above this line only)

3. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों/अध्यक्षों को पद से मुक्त किये जाने के आधार बताइये।
Explain the grounds for disqualification of the members/chairmen of the Union Public Service Commission from their posts.

2

- सिद्ध कदाचार व अक्षमता के मामले सुप्रीम कोर्ट की जाँच के पश्चात्
- दिवालिया, मानसिक-शारीरिक रूप से अक्षम, लाभ का पद आदि आधारों पर बिना सुप्रीम कोर्ट की जाँच के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं।

(Write above this line only)

4. राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए सम्पन्न चुनावों में विजयी सीटों की दलवार स्थिति को लिखिए।
Write the party-wise position of winning seats in the elections held for the 16th Assembly of Rajasthan.

(Write above this line only)

5. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'पब्लिक ट्रस्ट' का सिद्धान्त।
The principle of 'Public Trust' propounded by the Supreme Court.

1/2

पब्लिक ट्रस्ट से आशय किसी संस्था / सरकार के प्रति
जनता की विश्वसनीयता से है।
कुछ संसाधन जैसे- हवा, पानी, जंगल, आदि निजी स्वामित्व का
विषय वस्तु बनना अन्यायपूर्ण होगा।
वाद - एम० सी० मेहता vs कमलनाथ - 1997

(Write above this line only)

6. संविधान के 'अनुच्छेद-231' पर टिप्पणी लिखिए।
Comment on 'Article 231' of the Constitution.

(Write above this line only)

7. 'डी-हाईफनेशन नीति' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'De-hyphenation policy'.

2

डी-हाईफनेशन नीति इजराइल व फिलीस्तीन के साथ भारत की कूटनीति को संदर्भित करती है। इसके अनुसार भारत दोनों देशों के साथ पृथक्‌ व स्वतंत्र संबंध रखता है जो उसके राष्ट्रहित से प्रेरित है।

(Write above this line only)

8. हाल ही में सुर्खियों में रहा 'अनुच्छेद-44'
'Article 44', was recently seen in the news.

2

अनुच्छेद-44 का संबंध भारतीय संविधान के भाग-4 में वर्णित एक नीति निदेशक तत्व से है जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा सभी नागरिकों के लिए एकसमान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात तलाक, विवाह, उत्तराधिकार आदि मामलों में सभी धर्म के व्यक्तियों को समान अधिकार/कानून।

(Write above this line only)

9. 'भारत का राज्यक्षेत्र', 'भारत संघ' से बड़ी अवधारणा है। कैसे?
'Territory of India' is a bigger concept than 'Union of India'. How?

2

चूंकि भारत संघ 'राज्य' एवं 'केंद्र शासित प्रदेश' नामक इकाईयों से मिलकर बना है (अनु०-1) जबकि भारत के राज्यक्षेत्र में इन दो इकाईयों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है जो भारत सरकार के अधिकार में आते हैं (eg- विजित प्रदेश)

(Write above this line only)

10. प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द 'समानता' पर टिप्पणी लिखिए।
Comment on the word 'Equality' mentioned in the Preamble.

(1)

↳ लोकतान्त्रिक विचारधारा का सारतत्व

समानता → विशेषाधिकारों का अभाव।

→ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, रंग, आदि आधारों पर किसी के साथ भेदभाव ना करना।

→ सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता का न होना।

कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति को बराबर होने की बात

(Write above this line only)

11. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के सन्दर्भ में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों को लिखिए।
Write the directive principles mentioned in the context of promotion of peace and security at the international level.

(2)

भारतीय संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद-51 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है।

इसके अलावा – दो देशों के बीच विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करना

– अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि, समझौतों का सम्मान

(Write above this line only)

12. 'ग्लोबल गेटवे' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Global Gateway'.

(2)

ग्लोबल गेटवे → यह यूरोपियन यूनियन (EU) द्वारा चीन की BRI परियोजना को प्रतिसंतुलित करने हेतु शुरू की गई परियोजना पहल है।

↳ इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का निर्माण व ऋण सहायता शामिल है।

(Write above this line only)

13. राजनीतिक अवसरवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
Explain the concept of political opportunism.

2

राजनीति के क्षेत्र में किसी राजनेता / राजनीतिक दल द्वारा लाभ के अवसर के अनुरूप गतिविधियों / कार्यों का संचालन करना ही राजनीतिक अवसरवाद कहलाता है।
उदा०— दल बदल इसी का एक रूप है। जिस पार्टी में लाभ दिखा उसी में शामिल हो जाना।

(Write above this line only)

14. 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Procedure established by law'.

2

यह न्यायिक पुनरावलोकन का ही एक रूप है जिसमें न्यायपालिका किसी कानून के संबंध में केवल यह जांच कर सकती है कि उस कानून के निर्माण के समय संसद/विधानमण्डल द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। कानून अपने आप में उचित है या नहीं एवं कार्यपालिका आदेशों की जांच नहीं कर सकती।
eg- ब्रिटेन में

(Write above this line only)

15. भारतीय सन्दर्भ में 'पंथनिरपेक्षता' का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए।
Explain the meaning of 'Secularism' in the Indian context.

2

भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्षता से आशय है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना जोकि सर्वधर्मसमभाव के सिद्धांत पर आधारित है।
→ राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं
→ किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं
→ सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता
↳ अनावश्यक रूप से धर्म में हस्तक्षेप नहीं परन्तु यदि मूलाधिकारों के हनन का प्रश्न हो तो हस्तक्षेप उचित। eg. - ट्रिपल तलाक

शब्द सीमा का ध्यान रखें।

(Write above this line only)

16. विधानसभा व विधानपरिषद के मध्य किसी विधेयक को लेकर उत्पन्न होने वाले गतिरोध के कारणों को उल्लेखित कीजिए।
Mention the reasons for the deadlock arising between the Legislative Assembly and the Legislative Council regarding a bill.

1½

(iii) विधान परिषद द्वारा 3 माह से अधिक समय तक रोक कर रखना

यदि विधानसभा द्वारा किसी विधेयक को पारित कर विधान-परिषद में भेजा जाता है तब - (i) विधानपरिषद द्वारा उसे स्वीकृति न दी जाए (ii) विधेयक में विधानपरिषद द्वारा संशोधन सुझाए जाए परन्तु इन्हें विधानसभा स्वीकार ना करे तो दोनों के बीच गतिरोध होता है परन्तु संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, विधानसभा की कार्यवाही ही मान्य।

(Write above this line only)

17. संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित पदाधिकारियों के पद उल्लेखित कीजिए।
Mention the posts of the officials mentioned in the Third Schedule of the Constitution.

1½

1. संसद के सदस्य — SC व HC के न्यायधीश
2. विधानसभा के सदस्य — केन्द्र या राज्य के मंत्री
3. उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

} इनके पद के लिए शपथ का प्रारूप (3rd अनुसूची में)

(Write above this line only)

18. संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में उल्लेखित किन्हीं चार विषयों का उल्लेख कीजिए।
Mention any four subjects mentioned in the context of local self-government mentioned in the 12th Schedule of the Constitution.

2

1. शहरी क्षेत्र में स्वच्छता
2. पेयजल
3. जन्म-मृत्यु आंकड़ों का पंजीकरण
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन - लाभार्थी पहचान - राशन दुकान संचालन etc.

(Write above this line only)

19. 'संसदीय सचिव' पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on 'Parliamentary Secretary'.

विधानमण्डल के सदस्य, गैर संवैधानिक पद
नियुक्ति - मुख्यमंत्री

(0)

संसद के दोनों सदनों में प्रशासनिक कार्यों (दैनिक बैठकों का आयोजन, बैठक की कार्यवाही की रिकोर्ड-प्रकाशन, etc) के संचालन के नेतृत्व हेतु पीठासीन अधिकारियों द्वारा महासचिव/संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है।

कार्य - वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करना

(Write above this line only)

20. नगरपालिका एवं नगर परिषद की किन्ही तीन विधायी शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
Mention any three legislative powers of Municipality (Municipal Corporation) and City Council (Municipal Council).

(1½)

1. अपने क्षेत्र के विधानसभा/लोकसभा सदस्य (MLA/MP) को पदेन सदस्य के रूप में नामित करना।
2. अपने क्षेत्र की विकास योजना तैयार करना
3. विभिन्न नियम-विनियमों का निर्माण।

2. नियमों में परिवर्तन (Write above this line only) (3) लाइसेन्स जारी करना

21. संविधानवाद
Constitutionalism

राज्य व्यवस्था का स्वरूप जो संविधान के अन्तर्गत हो
सरकार के अधिकार सीमित व विधि के अधीन हो

(½)

संविधान के आदर्शों, मूल्यों, सिद्धान्तों व इसमें उल्लिखित बातों का सम्मान करना व पूर्ण निष्ठा से पालन करना ही संविधानवाद कहलाता है। संवैधानिक शासन, लोकतंत्र,

इसमें किसी समस्या का समाधान संवैधानिक तरीकों से ही करने का प्रयास किया जाता है।

(Write above this line only)

22. अभिलेख न्यायालय
Court of Record

(2)

अनु. 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति दी गई। तात्पर्य → (1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को आधार मानकर ही सुनवाई की जाएगी।
(2) सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर दण्ड देने की शक्ति।
↳ सभी उच्च न्यायालय को भी यह शक्ति प्राप्त है।

(Write above this line only)

23. विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विदेशों से धनप्रेषण प्राप्ति वाले चार शीर्ष राष्ट्रों के नाम लिखिए।
According to the report released by the World Bank, name the top four countries receiving remittances from foreign countries in the year 2023.

(1)

1. भारत 2. ~~पाकिस्तान~~ मैक्सिको
3. चीन
4. ~~बांग्लादेश~~ फिलीपीन्स

(Write above this line only)

24. 'खेलो इंडिया पैरा गेम्स-2023'
'Khelo India Para Games-2023'

(Write above this line only)

25. जलवायु परिवर्तन सूचकांक-2024 में शीर्षतम व निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाले तीन-तीन राष्ट्रों के नाम लिखिए।
Write the names of the three countries that have secured the top most and lowest positions in the Climate Change Index-2024.

0

~~शीर्षतम → चीन > भारत > USA~~

~~निम्नतम → नार्वे > स्वीडन~~

शीर्ष — निम्न

4 डेनमार्क — 67. सऊदी अरब

5 एस्टोनिया — 66. ईरान

6 फिलीपीन्स — 65. UAE

(Write above this line only)

Part - B

Note : Answer the following questions in 50 words. Each question carries 5 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

1. मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है तथा उत्तरदायित्व के इस पक्ष में निहित अर्थों को समझाइये।
To whom is the collective responsibility of the Council of Ministers and explain the meanings inherent in this aspect of responsibility.

4

(i) मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकारता है।

संविधान के अनुच्छेद-75 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत जवाबदेही राष्ट्रपति के प्रति होती है परन्तु सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। इसका तात्पर्य है मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत बना रहना आवश्यक है। यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे तुरन्त इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के अस्तित्व हेतु उनका लोकसभा में विश्वास बना रहना आवश्यक है।

(Write above this line only)

2. सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक अथवा मूल क्षेत्राधिकार को उल्लेखित कीजिए।
Mention the original jurisdiction of the Supreme Court.

(4)

सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक /मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि कोई मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु लाया जाएगा (इससे पूर्व किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ कोर्ट में नहीं)

इसमे निम्न मामले शामिल (5) 'विधि का सारत्व का प्रश्न हो'

① केंद्र-राज्य विवाद ② राज्य-राज्य विवाद ③ केंद्र व राज्य v/s राज्य विवाद

④ राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद

इसमे संविधानपूर्व के केंद्र-राज्य / राज्य-राज्य विवाद नहि आते हैं।

(Write above this line only)

3. "राजस्थान में आजादी के बाद जातियों के राजनीतिकरण का स्वरूप बदल रहा है।" स्पष्ट कीजिए।
"The nature of politicization of castes is changing after independence in Rajasthan." Explain.

(3)

रजनी कोठारी

जातियों के राजनीतिकरण से आशय है राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से जातिगत पहचान को उभारकर अधिक से अधिक वोट लेने का प्रयास करना।

प्रथम विधानसभा राजपूतों का वर्चस्व

→ स्वरूप मे बदलाव → 1950-70 के दशक के समय जाट, ब्राह्मण, राजपूत जातियाँ के आधार पर राजनीतिकरण का प्रयास किया जाता था परन्तु 1990 के बाद इसमे बदलाव आया है अब मीणा, गुर्जर, सैनी, यादव, आदि वोटबैंक इसका आधार बने है। जाट → शेखावाटी व भरतपुर धौलपुर

कारासित नीटे

मीणा → ... , गुर्जर आन्दोलन

(Write above this line only)

4. वर्तमान में रूस-चीन के मध्य मजबूत होते सामरिक रिश्ते भारत के लिए किस प्रकार से चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं?
How can the currently strengthening strategic relations between Russia and China present challenges for India?

(3)

ऐतिहासिक रूप से रूस भारत का मित्र रहा व सहयोगी रहा है। दोनों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी रही है। जबकि चीन सदैव ही भारत के हितों के लिए खतरा रहा बना हुआ है। अतः रूस-चीन नजदीकी → रूस द्वारा चीन को हथियार बेचना — सुखोई-35, S-400

↳ भारत-रूस संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। (संयुक्त युद्धाभ्यास)

↳ चीन की BRI परियोजना को और बल मिलेगा।

↳ भारत की चीन को काउंटर करने की कोशिश कमजोर पड़ेगी।

↳ भारत के विरुद्ध रूस-चीन-पाक गठबंधन बनने का खतरा चीन की तालिबान वार्ता

↳ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व में कमी।

(Write above this line only)

निष्कर्ष — भारत के समक्ष चीन का स्थान

5. मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए।
Explain the relationships between Fundamental Rights and Directive Principles.

($3\frac{1}{2}$)

(FR) मौलिक अधिकार नागरिकों को राजनैतिक लोकतंत्र उपलब्ध कराते हैं वहीं नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उद्देश्य देश में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इस प्रकार दोनों परस्पर पूरक हैं। यद्यपि समय-2 पर दोनों के बीच टकराव हुआ है जैसे- चंपकम दोराई राजन वाद, 1951, गोलकनाथ वाद, 1967, केशवानंद भारती, 1973। व्यक्ति व समाज में सन्तुलन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेनका गांधी वाद, 1980 में FR व DPSP में समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत दिया गया। दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग

वर्तमान स्थिति → • सामान्यतः दोनों में संतुलन मौलिक अधिकारों के वाद-विवाद में DPSP का सहारा लिया जाता है

• विरोध हो तो FR > DPSP

निष्कर्ष - ?

• Art-39(b), 39(c) के DPSP > FR - Art-14, 19, 31

(Write above this line only)

6. "भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण है।" उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। लचीला - इंग्लैण्ड

"The Indian Constitution is a combination of rigidity and flexibility." Explain the above statement.

(4)

कठोर संविधान - USA

भारतीय संविधान के कठोर होने का तात्पर्य है कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करना अत्यंत कठिन है जैसे- राष्ट्रपति निर्वाचन, उच्चतम व उच्च न्यायालय अधिकारिता, केंद्र-राज्य संबंध आदि। इनमें संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत (2/3) व साथ ही आधे राज्य विधानमण्डलों की सहमति आवश्यक है। परन्तु इसी संविधान में नागरिकता (Art-11), नए राज्यों का गठन (Art-...), 5वीं-6वीं अनुसूची आदि उपबंधों में साधारण बहुमत से ही संशोधन सम्भव है। इस प्रकार भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है।

(Write above this line only)

(3) विशेष बहुमत - दोनों सदनों ... 2/3

7. "विधानसभा जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है न कि विधानपरिषद।" स्पष्ट कीजिए।

"The Legislative Assembly is the real representation of the people and not the Legislative Council." Explain.

(4)

→ जन महत्वकांक्षा का प्रतीक, कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव ...

वयस्क मताधिकार

विधानसभा राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन है जिसके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित किया जाता है जबकि विधानपरिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है एवं इनका चुनाव जनता द्वारा न होकर नगर निकाय व पंचायतों के सदस्य करते है। दूसरा, विधानपरिषद की शक्तियाँ भी विधानसभा से कम है। विधानसभा जोकि वास्तविक जनप्रतिनिधि सदन है, विधेयक पारित करने में असली शक्ति रखता है। अतः विधानसभा जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है न कि विधानपरिषद।

(Write above this line only)

निष्कर्ष: -

8. "विधानसभा की बैठक का स्थगन विधानसभा के सत्रावसान की तुलना में सीमित क्षेत्र/प्रक्रिया रखता है।" उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।
"Adjournment of the meeting of the Legislative Assembly has limited scope/procedure as compared to prorogation of the Legislative Assembly." Explain the above statement.

(Write above this line only)

9. उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रचलित 'कॉलेजियम प्रणाली' के उद्भव/विकास पर टिप्पणी लिखिए।
Write comment on the origin/development of the 'Collegium System' prevalent in the context of appointment of judges of the higher judiciary.

(5)

मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति (उच्चतर न्यायपालिका में) की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के CJI (मुख्य न्यायाधीश) से परामर्श की बात कही गयी थी। परन्तु सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णय – (संविधान में उल्लेख नहीं)

प्रथम न्यायाधीश मामला, 1981 → CJI का परामर्श मानने को राष्ट्रपति बाध्य नहीं

द्वितीय जज मामला 1993 → CJI + 2 वरिष्ठ जज की परामर्श बाध्यकारी — परामर्श का मतलब 'सहमति'

तृतीय जज मामला 1998 → 1 (CJI) + 4 जज का कॉलेजियम का परामर्श

1998 में जन्मी) इस कालेजियम प्रणाली को ही उच्च न्यायालय में भी अपनाया गया परन्तु इस कालेजियम में – CJI + High court का CJ + 1 वरिष्ठ जज

(Write above this line only)

10. प्रस्तावना जो संविधान की कुंजी है, में उल्लेखित लक्ष्यों/उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the goals/objectives mentioned in the Preamble which is the key to the Constitution.

(5)

डॉ. बी. आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। यह संविधान के मूलभूत आदर्शों/सिद्धान्तों व उद्देश्यों को दर्शाती है।

प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्य →
- न्याय – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
- समानता – प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता
- स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना
- बंधुता → देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखने वाली
- → राज्य का स्वरूप – संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य

(Write above this line only)

11. "भारत में संसदीय नियत्रंण वास्तविक की बजाय सैद्धान्तिक है।" उक्त कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
"Parliamentary control in India is theoretical rather than practical." Present arguments in favor of the above statement.

(3)

सरकार/मंत्री का संसद के प्रति उत्तरदायी
संसद का बड़ा आकार, विधायी नेतृत्व का कार्यपालिका
निर्णि
प्रशासन पर अप्रभावी नियंत्रण

यहाँ कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण की बात की गई है। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका विधायिका (संसद) का ही एक भाग होती है अर्थात विधायिका में ही बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। अतः यदि कार्यपालिका के पास संसद में बहुमत मौजूद है तो वह अपने पार्टी एजेण्डे के अनुसार सभी विधेयक आसानी से पारित करवा सकती है (अत्यधिक अध्यादेश जारी करना) चाहे विपक्ष व अन्य पार्टियों की असहमति हो (विपक्ष का अभाव)। अतः भारत में संसदीय नियंत्रण सैद्धांतिक है ना कि वास्तविक।

निष्कर्ष

(Write above this line only)

12. संविधान के अनुच्छेद-72 में उल्लेखित राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों पर टिप्पणी कीजिए।
Comment on the pardoning powers of the President mentioned in Article 72 of the Constitution.

(4)

संविधान के अनुच्छेद-72 मे राष्ट्रपति को 5 क्षमादान शक्तियाँ प्रदान की गई है- (संघ के कानूनो के अंतर्गत)

① क्षमा - इसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है। ↳ व्यक्ति दोषमुक्त स्थिति मे।

② लघुकरण → सजा की प्रकृति मे बदलाव करना eg. - कठोर कारावास को साधारण कारावास मे बदलना

③ परिहार → सजा की अवधि कम करना eg.- आजीवन कारावास को 10 वर्ष करना

④ विराम → विशेष परिस्थितियों (गर्भवती महिला, दिव्यांग) मे सजा की प्रकृति व अवधि दोनो मे कमी / परिवर्तन

⑤ प्रविलंबन → मृत्युदण्ड के मामले मे अस्थायी रोक
अस्थाई (अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन मे रोक

(Write above this line only)

13. 'स्वतंत्रता के अधिकार' के अन्तर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकार व उन पर आरोपित युक्तियुक्त प्रतिबंधों को उल्लेखित कीजिए।
Mention the fundamental rights mentioned under 'Right to Freedom' and the reasonable restrictions imposed on them.

(5)

संविधान का अनुच्छेद-19(1) भारतीय नागरिकों को निम्न स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है-

अधिकार	युक्तियुक्त निर्बंधन
Art-19(1)(a) - वाक्-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता →	Art-19(2) → राज्य की सुरक्षा, एकता-अखण्डता, विदेशी राज्य के साथ संबंध, मानहानि, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन
Art-19(1)(b) → शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता →	Art-19(3) → लोक व्यवस्था, नैतिकता, जनहित
Art-19(1)(c) → संघ बनाने की →	Art-19(4) → लोक व्यवस्था, नैतिकता
Art-19(1)(d) → पूरे देश मे निर्बाध विचरण की; Art-19(1)(e) → कही भी निवास →	Art-19(5) → जनहित, जनजाति के हित मे
Art-19(1)(g) → कोई भी व्यापार / वृत्ति / व्यवसाय →	Art-19(6) → जनहित

(Write above this line only)

14. मंत्रिमण्डल व मंत्रिपरिषद में मूलभूत अन्तर लिखिए।
Write the basic differences between Cabinet and Council of Ministers.

(3)

मंत्रिपरिषद	मंत्रिमंडल
• संविधान के उपबंधों (Art-75) के तहत गठन (Art.-74)	• संविधान में गठन का प्रावधान नहीं केवल एक जगह (Art-352) में उल्लेख
• आकार -निश्चित (लोकसभा सदस्य संख्या का 15% max)	• आकार — निर्धारित नहीं लघु निकाय (कैबिनेट मंत्री)
• इसका आकार बड़ा होता है।	• मंत्रिपरिषद का ही एक भाग अतः छोटा आकार
• सभी मंत्री सम्मिलित < कैबिनेट राज्यमंत्री उपमंत्री	• केवल महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री
• व्यापक अवधारणा - कार्यों का निर्धारण	• संकीर्ण अवधारणा वास्तविक शक्ति
• एकसाथ बैठक नहीं मंत्रीमंडल द्वारा शक्तियां	• नियमित बैठक - महत्वपूर्ण निर्णय राजनीतिक निर्णय

(Write above this line only)

15. वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीयों द्वारा पश्चिम एशिया व उत्तरी अमेरिकी देशों में सामना की जाने वाली चुनौतियों को लिखिए।
Write the challenges currently faced by Indian diaspora at the global level in West Asia and North American countries.

($3\frac{1}{2}$)

वर्तमान में प्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में विभिन्न देशों में फैले हैं परन्तु इनके द्वारा कई चुनौतियों का सामना किया जा रहा है -

पश्चिम एशिया	उत्तरी अमेरिका
• श्रमिकों की कठिन कार्य परिस्थितियाँ	• वीजा की समस्या e.g. - USA में H1B-visa विवाद
• कड़े व विशिष्ट श्रम कानून	• कौशलयुक्त श्रम की ही मांग
• अधिकारों का हनन	• नस्लीय भेदभाव
• प०एशियाई देशों के बीच आपसी तनाव / संघर्षों के कारण सुरक्षा का खतरा	- चिकित्सा, शिक्षा, वेतन - अनुबंध शर्तों का उल्लंघन - परिवार की स्थिति ...

- शिक्षा - चुनौती करार
- निराकृत कानून
- तेल की कीमतों में गिरावट

(Write above this line only)

16. वर्तमान में भारत-भूटान के मध्य संबंधों में विद्यमान चुनौतियों को लिखिए।
Write the challenges existing currently in the relations between India and Bhutan.

③

– 1949 मैत्री संधि

भूटान के भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं एवं भूटान की सुरक्षा, विदेशी मामले व संचार जैसे विषय भारत पर आश्रित हैं। परंतु वर्तमान में दोनों के संबंधों में कुछ चुनौतियाँ –

① BBIN मोटरवाहन समझौते पर भूटान द्वारा हस्ताक्षर नहीं

② भूटान-चीन सीमा विवाद मामले में भूटान व चीन के बीच वार्ता प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है परंतु भारत से परामर्श नहीं।

↳ भूटान के विदेश मंत्री का चीन का दौरा

पर्यावरणीय मुद्दे

③ चीन द्वारा भूटान-भारत सीमा के पास बुनियादी अवसंरचना विकास

– भूटान की व्यापार निर्भरता –

– भूटान की जल विद्युत परियोजना

(Write above this line only)

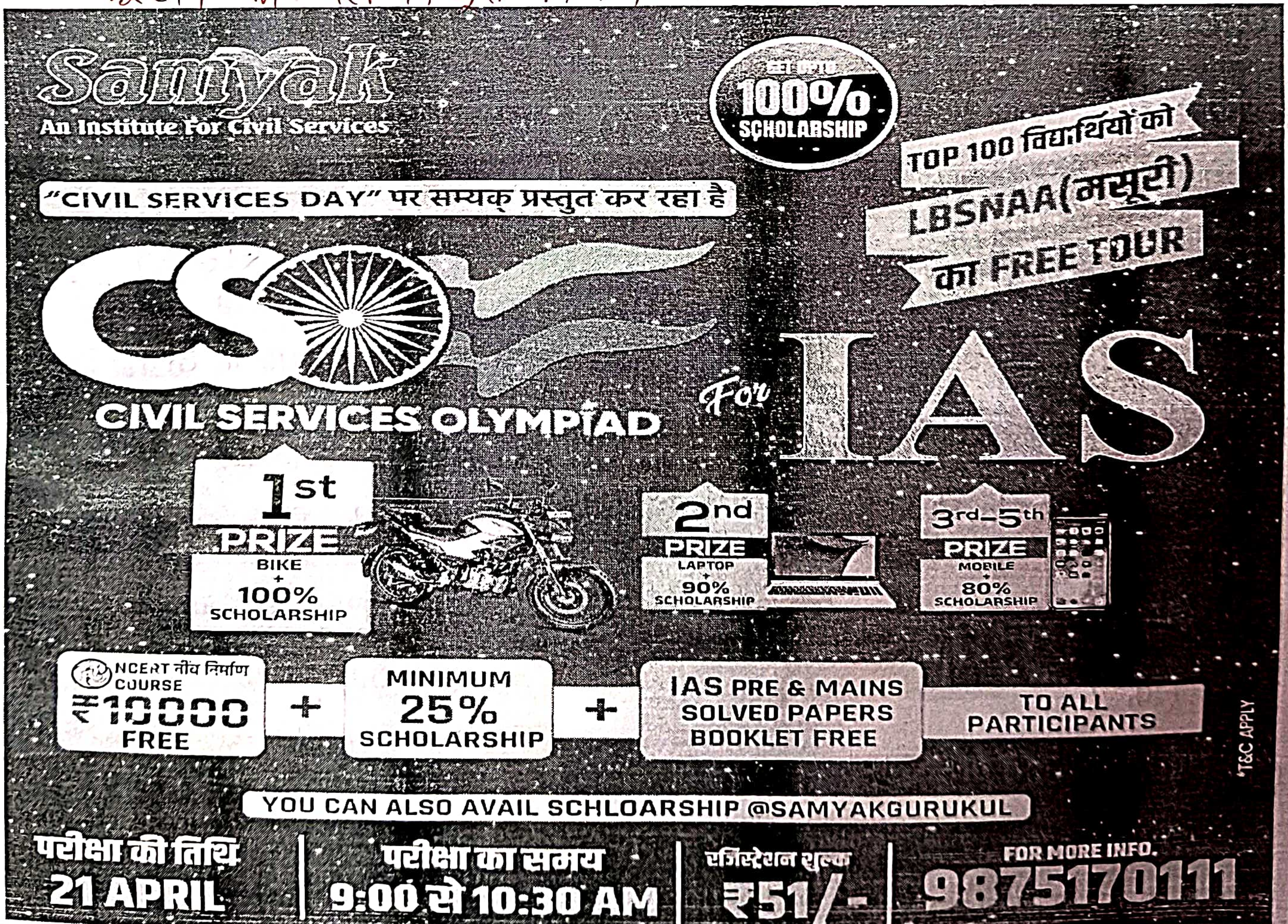

Part - C

Note : Answer the following questions in 100 words. Each question carries 10 marks.

नोट : निम्न प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. राज्यपाल का पद संवैधानिक होते हुए भी नियुक्ति की प्रक्रिया के कारण कमतर आंका जाता है, इस सन्दर्भ में राज्यपाल के निर्वाचन के पक्ष व विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।

3+4 = 7

Despite being constitutional, the post of Governor is undermined due to the appointment process. In this context, give arguments in favor and against the election of the Governor.

3 भारतीय संविधान में अनुच्छेद -153 के तहत राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है एवं इसे राज्य के संवैधानिक प्रमुख का दर्जा प्राप्त है। परन्तु इसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं मनमाने ढंग से अपदस्थ भी कर दिया जाता है जिससे इसके पद का महत्व कम आंका जाता है।

दोहरी भूमिका - ① राज्य का संवैधानिक प्रमुख ② केन्द्र का प्रतिनिधि

राज्यपाल निर्वाचन : पक्ष में तर्क

- जिस प्रकार राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य के। अतः राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल पद हेतु भी निर्वाचन आवश्यक। 4
- अलग-अलग दल की सरकार होने से राज्यपाल व मुख्यमंत्री में टकराव
- वर्तमान में राज्यपाल पर केन्द्र के एजेण्ट के रूप में कार्य करने के आरोप लगाए जाते हैं। निर्वाचित सरकार की अवहेलना, विधेयक को राष्ट्रपति के आरक्षित
- निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित हो सके।
- राज्यपाल अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएगा।

विपक्ष में तर्क

- निर्वाचित पद होने से राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच शक्ति संघर्ष↑ (संसदीय शासन व्यवस्था के प्रतिकूल) (अलगाववाद की धारणा)
- चूँकि राज्यपाल केवल औपचारिक प्रमुख, अतः निर्वाचन पर व्यय अनावश्यक
- प्रायः राज्य के बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। अतः जनता के बीच लोकप्रिय नहीं। केन्द्र का नियंत्रण मुश्किल

वर्तमान राज्यपाल पद के निर्वाचन से अधिक आवश्यक इस पद के राजनीतिकरण को रोकना है तथा कार्यकाल की सुरक्षा देना। इस सन्दर्भ में सरकारिया आयोग की सिफारिशें लागू

(Write above this line only)

2. राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना का लक्ष्य बताते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष आने वाली बाधाओं तथा उनके शमन के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लिखिए।

While explaining the aim of establishing the National Integration Council, write down the obstacles facing national integration and the steps to be taken to mitigate them.

2+2
(4)

1961

राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना का लक्ष्य →

↳ स्वतंत्रता पश्चात देश में सांप्रदायिक माहौल था। अतः नागरिकों में एकता का भाव स्थापित करने, बंधुता बढ़ाने एवं राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बनाए रखने हेतु

(विविधता में एकता, धार्मिक स्वतंत्रता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता को कम करना)

राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष बाधा

↳ विभिन्न धर्मों मुख्यतः हिंदू व मुस्लिम लोगों के बीच सौहार्द्र ?

↳ भाषायी आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग

↳ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का मुद्दा

↳ राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता

(- साम्प्रदायिकता, - क्षेत्रवाद, - भाषा विवाद, - भ्रष्टाचार, - जातिवाद, उग्रवाद, - नक्सलवाद, - दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली)

उपाय / कदम → राज्य पुनर्गठन (भाषायी आधार पर)

① उच्च व समावेशी आर्थिक विकास

② रोजगार का सृजन

③ भाषायी ~~विविधता~~ विवाद का कम करना

④ भ्रष्टाचार खत्म

(Write above this line only)

3. नीति निदेशक तत्वों के आलोचनात्मक बिन्दुओं को लिखते हुए इनको लागू किये जाने के सन्दर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बताइये।

Critically analyse the points of the Directive Principles and tell the steps taken by the government regarding their implementation.

(9)

भारत मे नागरिकों को सामाजिक - आर्थिक लोकतंत्र व न्याय को उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ संविधाननिर्माताओं द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के पूरक के रूप मे समावेशित किया गया (भाग -4 ; Art:36-51)

निर्देश भाग
रूढ़िवादी चरक

DPSP: आलोचना
1. न्यायालय मे प्रवर्तनीय नही
2. राज्य के लिए इन्हें लागू करना बाध्यकारी नही।
3. इनका स्वरूप आदर्शवादी है
4. कई स्थानों पर अर्थ मे अस्पष्टता
5. कुछ DPSP मे रूढ़िवादी तत्व eg. - शराबबंदी

इन्हें लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय -2 पर कानूनों का निर्माण किया गया है -

↳ Art-48(क) → वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

↳ Art-39(A) → निःशुल्क विधिक सहायता → विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

↳ Art-40 → पंचायतों के सशक्तीकरण हेतु संवैधानिक दर्जा
भूमि सुधार, औद्योगिक 73वाँ, 74वाँ संविधान संशोधन
प्रिवी पर्स खत्म

↳ Art-46 → SC व ST के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम - छुआछूत उन्मूलन

↳ Art-47 → लोकस्वास्थ्य → आयुष्मान भारत, PM-JAY

↳ Art-49 → सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

⇒ 1st संविधान संशोधन → Art-39(ख),(ग) | - AMSAR Act

इस प्रकार सरकार द्वारा DPSP को लागू करने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए।

1. "राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से व्यक्तियों के अधिकार व राज्यों की स्वायत्तता पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं।" उक्त कथन को स्पष्ट करें।

"The declaration of national emergency has far-reaching effects on the rights of individuals and the autonomy of states." Explain the above statement.

7

→ प्रावधान - अनुच्छेद 352 से 360

राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। इससे न केवल राज्यों की स्वायत्तता में कमी आती है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकार भी प्रभावित होते हैं। राज्य को असमान्य स्थिति से निपटने के लिए

उद्देश्य - एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता संविधान की सुरक्षा

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव →

Art-358 → Art-352 के तहत राष्ट्रीय आपात के समय Art-19 (स्वतन्त्रता का अधिकार) स्वतः निलंबित

Art-359 → राष्ट्रपति आपातकाल के समय Art-20, 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद-352 - राष्ट्रीय आपातकाल

राज्य स्वायत्तता पर प्रभाव ① संघीय शासन का स्वरूप - एकात्मक
② विधानमण्डल के कार्यकाल में वृद्धि

- राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है।
- संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है।
- राज्यों को केंद्र द्वारा विविध निर्देश दिए जा सकते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल भारत के संघीय चरित्र के प्रतिकूल है व राज्य स्वायत्तता को कम करता है। परन्तु आपात स्थिति (युद्ध, आक्रमण) के समय आवश्यक है। किन्तु राज्य स्वायत्तता व मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष -

(Write above this line only)

5. केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य टकराव/विवाद के बिन्दुओं पर लेख लिखते हुए टकराव/विवाद शमन के सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

While writing about the points of conflict/dispute between the Central Government and the State Governments, present suggestions for mitigating the conflict/dispute.

8

यद्यपि भारतीय संविधान देश में संघीय प्रणाली की स्थापना करता है जिसमें केंद्र व राज्य की शक्तियों को स्पष्ट रूप से बाँटा गया है (Art -246, 7वीं अनुसूची) परन्तु कई बार दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है Article - 356 का दुरुपयोग

1. समवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण में अखिल भारतीय सेवाएं
2. आपातकाल के दौरान राज्य सरकारों को भंग करना
3. राज्यपाल द्वारा विधानसभा के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना (Art - 200) • शक्तियों का असमान वितरण
4. राज्यों में बिना अनुमति केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती
5. राज्यों में CBI हस्तक्षेप भाषा विवाद, जल विवाद, सीमा विवाद
6. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 7. केंद्र द्वारा वित्त आयोग की सलाह पर राज्यों को वित्त संसाधनों का आवंटन
8. राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग
वित्तीय निर्भरता

शमन के उपाय

- समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण से पूर्व अंतर-राज्य परिषद में चर्चा • सहकारी नीतियों को प्रोत्साहन
- राज्यपाल द्वारा विधेयक आरक्षित करने के स्पष्ट आधार बताए जाएं
- अत्यावश्यक होने पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाए
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा • स्पष्ट भूमिका • संयोगात्मक संवाद

स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंध से ही राष्ट्र विकास संभव है।

Write above this line only

6. निम्न बिन्दुओं पर लेख लिखिए/टिप्पणी कीजिए।/Write article/comment on the following points.

1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व इसके कारण उत्पन्न प्रभाव/International terrorism and its resulting effects

2. इजराय़ल-हमास संघर्ष की निरन्तरता के भारत व विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव/Impact of continuation of Israel-Hamas conflict on India and the world

4+3
(7)

② इजराइल-हमास संघर्ष के प्रभाव

भारत पर | विश्व पर

- ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित - भारत अपनी तेल जरूरतों का अधिकांश खाड़ी देशों से आयात
- यूरोप के साथ व्यापार प्रभावित
- प. एशियाई देशों से संबंध प्रभावित, कूटनीतिक स्थिति कमज़ोर
- प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा
- रक्षा संबंध प्रभावित - भारत द्वारा इजराइल से मिसाइल, ड्रोन्स आयात किए जाते हैं।

- हमास द्वारा इजराइली नागरिकों को बंधक बनाना - मानवाधिकार संकट
- आपूर्ति श्रृंखला में बाधा
- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ⇒ मुद्रास्फीति का खतरा
- UN की उपयोगिता पर संशय
- वैश्विक शिपिंग संचालन
- वैश्विक आर्थिक मंदी। प्रभावित

(4)

① अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद → जब आतंकवादी संगठनों द्वारा एक से अधिक देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है।

वैश्विक स्तर पर शस्त्र हिंसा
↳ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैचारिक

प्रभाव
⇓
विदेशी निवेश पर प्रभाव

(3)

↳ वैश्विक स्तर पर नागरिकों में भय व आतंक का माहौल
↳ बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु (आतंकी हमले से)
↳ अवसंरचनात्मक हानि - बड़ी इमारतें, शहर तबाह
↳ मानवाधिकार संकट - विशेषतः बच्चे, वृद्ध, महिलाएं प्रभावित
↳ शरणार्थी संकट - वैश्विक व्यापार व वाणिज्य प्रभावित
↳ खाद्यापूर्ति, नागरिक आपूर्ति प्रभावित, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ना

7. निम्न बिन्दुओं पर लेख लिखिए/टिप्पणी कीजिए।/Write short article on the following points.

1. न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा व सीमाएँ/Concept and limitations of the judicial review

2. राज्यपाल को विषयान्तर्गत जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य/Duties of the Chief Minister regarding giving relevant information to the Governor

2+4 = 6

SC की महत्वपूर्ण शक्ति

① न्यायिक पुनरावलोकन → इस अवधारणा के अनुसार न्यायालय द्वारा संसद द्वारा पारित अधिनियमों एवं कार्यपालिका आदेशों की समीक्षा की जा सकती है एवं उनके संविधान विरुद्ध होने पर उन्हें शून्य भी घोषित किया जा सकता है। उदा.- 99वाँ संविधान संशोधन (NJAC) → SC द्वारा शून्य

2

संविधान में उल्लेख नहीं

सीमाएं
① राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार
② मंत्रिपरिषद की सलाह की समीक्षा नहीं
③ संसद की कार्यवाही

सीमाएं
→ यह न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।
→ न्यायिक अतिसक्रियता को जन्म देता है जो कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को कमजोर करता है।
→ वास्तविक जनप्रतिनिधि सभा (संसद) की प्रतिष्ठा में कमी
→ संसद/कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तनाव को जन्म

② राज्यपाल को विषयान्तर्गत जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के निम्न कर्तव्य हैं— अनुच्छेदों का उल्लेख करो

(i) मुख्यमंत्री / कैबिनट बैठक द्वारा लिए गए निर्णय या किसी प्रशासनिक विनिश्चय के संबंध में राज्यपाल को यथाशीघ्र सूचित करना।

4

(ii) राज्यपाल द्वारा मांगे गए विषय के संबंध में जानकारी देना।

(iii) यदि किसी मंत्री द्वारा कोई विनिश्चय कर लिया गया परन्तु कैबिनेट में अभी चर्चा नहीं हुई तो राज्यपाल CM को इसे कैबिनट चर्चा में रखने हेतु कह सकता है। इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को करना CM का कर्तव्य है।

(iv) राज्यपाल द्वारा मांगी गई किसी रिपोर्ट की जानकारी

हिन्दी व्याकरण- पारिभाषिक शब्दावली व प्रारूप-लेखन-विज्ञप्ति

1. निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिन्दी पारिभाषिक शब्द लिखें? अंक- 10

(i) Ascertain – सुनिश्चित करना ✓ (1)

(ii) Brokerage - दलाली ✓ (1)

(iii) Conversion- रूपांतरण ✓ (1)

(iv) Inspection - जाँच ✓ (1)

(v) Memorandum - समझौता / ज्ञापन ✓ (1)

(vi) Negligence - उपेक्षा ✓ (1)

(vii) Ordinance - अध्यादेश ✓ (1)

(viii) Respondent -

(ix) Statement - कथन / वक्तव्य ✓ (1)

(x) Unofficial - अनौपचारिक ✓ (1)

3. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाँसवाड़ा की ओर से प्रायोगिक परीक्षाओं के स्थगन की विज्ञप्ति जारी कीजिए।

अंक- 1

English Grammer – Phrsal Verbs and Idioms

(A) Rewrite choosing the appropriate expression to form a meaningful sentence (Q. No. 1-10) Marks : 10×1 = 10

1. The administration helped to *using out/bring about* a peaceful settlement.

2. I *came by/came across* my old friend in the market yesterday.

3. His income has been *falling back/falling off* for the last two years.

4. The cat *got round/through* the kitchen window.

5. He cannot *keep back/from* the use of tobacco.

6. Big powers try to *fish in troubled sea/fish in troubled waters* in the third world countries.

7. By his kindness today, he has *made amends/made amendments* for his past insolence.

8. All separatist tendencies must be *nodded in the bud/nipped in the bud.*

9. Some clerks in this office are in the habit of taking *French leave/English leave.*

10. This progressive company gives a *sphere deal/a square deal* to this employees.

(A) Rewrite choosing the appropriate expression to form a meaningful sentence (Q. No. 1-10) Marks : 10×1 = 10

1. India and Pakistan are *at daggers drawn/at sixes and sevens* these days.

2. Mohan *looked blank/looked blue* as he had failed.

3. The local M.L.A. *fell from grace/hung in balance* when he was arrested for smuggling.

4. Our village is flying into a rage/has taken a quantum leap in the field of education.

5. Neighbours should not quarrel and should bury the hatchet/hang fire.

6. He is *at a stone's throw/all at sea,* he does not know what to do.

7. The government's promise to make the pare teachers permanent is only *an eye wash/a black leg.*

8. The first prize in lottery proved *a sine die/a windfall* for him.

9. Our captain scored a century on his *maiden appearance/exparte.*

10. One who works by *ins and outs/fits and starts* can't succeed.

Samyak
An Institute For Civil Services
GET UPTO 100% SCHOLARSHIP
"CIVIL SERVICES DAY" पर सम्यक् प्रस्तुत कर रहा है
TOP 100 विद्यार्थियों को LBSNAA(मसूरी) का FREE TOUR
CIVIL SERVICES OLYMPIAD For RAS
1st PRIZE BIKE + 100% SCHOLARSHIP
2nd PRIZE LAPTOP + 90% SCHOLARSHIP
3rd-5th PRIZE MOBILE + 80% SCHOLARSHIP
NCERT नींव निर्माण COURSE ₹10000 FREE
+
MINIMUM 25% SCHOLARSHIP
+
RAS PRE & MAINS SOLVED PAPERS BOOKLET FREE
TO ALL PARTICIPANTS
*T&C APPLY
YOU CAN ALSO AVAIL SCHLOARSHIP @SAMYAKGURUKUL
परीक्षा की तिथि 21 APRIL
परीक्षा का समय 9:00 से 10:30 AM
रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹51
FOR MORE INFO 9875170111